ग्रेप के पाखंड से लूट संभव है प्रदूषण नियंत्रण नहीं

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) शहर के पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सिर्फ ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) लागू करने के नाम पर जुर्माना वसूलने, उद्योग, निर्माण बंद करवाने से पर्यावरण स्वच्छ नहीं होने वाला। प्रदूषण न ही सैकड़ों किलोमीटर दूर पराली जलाए जाने का बहाना बना कर प्रदूषण फैलाने का इल्जाम किसानों के सिर रखने से दूर होगा। पहले प्रशासन सड़कों पर उड़ने वाली धूल, निर्माण और तोड़फोड़ के दौरान होने वाले पीएम 10 प्रदूषण पर नियंत्रण करे, साफ-सफाई और पर्याप्त बिजली-पानी आपूर्ति सुनिश्चित करे तो कुछ भला सकता है।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रशासन कोई काम करता नजर नहीं आ रहा। शहर की मुख्य सड़कें हों या हाईवे, सड़क के किनारे धूल ही धूल है, वाहनों के गुजरने से उड़ने वाली इस धूल के गुबार सभी जगह देखे जा सकते हैं। इस धूल को बैठाने के पानी छिड़कने नाम बिल बना बना कर जनता का पैसा डकारा जा रहा है, पानी कहीं नजर नहीं आता। नगर निगम हो या प्रशासन छिड़काव की मशीन, सड़क साफ करने वाली ट्रक माउंटेड झाड़ू, वाटर स्प्रे मशीन सभी उपलब्ध हैं लेकिन इनका इस्तेमाल कागजों पर होता है जमीन पर कम। नगर निगम के अधिकारियों का दावा है कि रोजाना रात में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रक माउंटेड झाड़ू मशीनों से सड़कों की सफाई कराई जाती है। इसके बावजूद शहर की सड़के धूल से पटी पड़ी हैं। ज्यादा धूल वाली जगहों पर वाटर स्प्रेयर से छिड़काव का भी दावा किया जाता है लेकिन ये कहीं काम करती दिखती नहीं। हां, इनके नाम पर लाखों रुपये के बिल लगाकर बंदरबांट होती है।

जेनरेटर चलाने पर पाबंदी लगा रखी है लेकिन न तो उद्योग को और न कारोबार को पर्याप्त बिजली आपूर्ति की जाती है। जेनरेटर नहीं चलाएंगे तो लाखों रुपये नुकसान होगा। अब कारोबारी, उद्यमी या तो काम बंद कर नुकसान झेलें या जेनरेटर चला कर मोटा जुर्माना भरें, प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर जुर्माना वसूल कर प्रशासन अपनी पीठ थपथपा लेगा।

धुआं रोकने के लिए उद्यम और कारोबार पर तो कड़ी रोक है लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों को कबाड़ियों द्वारा रोजाना जलाया जाने वाला कुड़ा कचरा नहीं दिखता। तार, लोहा, अल्युमिनियम जैसी धातुएं निकालने के लिए ये कबाड़ी प्लास्टिक, ई कचरा भी खुले आम जलाते हैं।

शहर में कृष्णा कॉलोनी, सरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर 21 में रेलवे लाइन के समानांतर, सेक्टर 29 पुल के पास कबाड़ी खुलेआम कचरा जला रहे हैं, इस कचरे की आग से उठता काला धुआं आम आदमी को कई किलोमीटर दूर से नजर आ जाता है लेकिन ग्रेप का ड्रामा करने वाले अधिकारियों को नजर नहीं आता। इन्हें नजर आता है सैकड़ों किलोमीटर दूर जलाई जाने वाली पराली का तथाकथित धुआं। सच्चाई यह है कि अब किसान पराली नहीं जलाता क्योंकि पराली की भी बाजार में अच्छी कीमत मिलने लगी है। फायदे का सौदा होने के कारण लगभग सभी किसानों ने पराली जलानी छोड़ दी है, लेकिन अधिकारियों को तो अपनी गर्दन बचाने के लिए किसी पर तो इल्जाम रखना है।

शहर में प्रदूषण के हालात ये हैं कि बृहस्पतिवार की शाम करीब साढ़े पांच बजे ये रिपोर्टर हार्डवेयर चौक से हाईवे के लिए निकला। सड़क पर धूल के गुबार थे, जाम होने के कारण बहुत से वाहन चालक पटरी और फुटपाथ से आगे निकल रहे थे, इन वाहनों से उड़ने वाली धूल से देखना भी मुश्किल हो रहा था। जाम के कारण हार्डवेयर चौक से बाटा पुल तक पहुंचने में बारह मिनट लगे, यहां आसमान में गाढ़ा काला धुआं उठता नजर आया।

पुल के टॉप पर पहुंचे तो बाईं ओर स्थित कृष्णा कॉलोनी में रेलवे लाइन के करीब बड़ी मात्रा में जलाए जा रहे कबाड़ से यह धुआं उठता नजर आया। यह धुआं हजारों जेनरेटर से निकलने वाले धुएं से अधिक काला और खतरनाक था रबर और प्लास्टिक जलने की बदबू नाक में घुस रही थी लेकिन अधिकारियों को यह धुआं नजर नहीं आया। वरिष्ठ समाजसेवी सुरेश गोयल कहते हैं कि प्लास्टिक जलाने से बिस फिनोल सहित अन्य खतरनाक रसायन हवा में घुलते हैं, इनसे कैंसर, दमा, त्वचा रोग जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं, आंखों के लिए भी इसका धुआं खतरनाक साबित होता है। वह कहते हैं कि अधिकारियों को उद्योग और कारोबार चौपट करना आसान लगता है न कि प्रदूषण फैलाने वाले कबाड़ियों पर अंकुश लगाना। कृष्णा कॉलोनी का उदाहरण तो अचानक सामने आ गया। इस तरह के काम तो पूरे शहर में प्रतिदिन हो रहे हैं। यही कारण है कि शहर में सांस, कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

शुक्रवार सुबह बाईपास रोड पर सेक्टर 29 पुल के पास भी कबाड़ियों ने करीब एक टन कचरे में आग लगा दी। इसका धुआं भी दूर दूर तक फैला, कुछ जागरूक नागरिकों ने 112 पर कॉल किया तो वह दिल्ली पुलिस को मिला और आग बुझाने कोई नहीं पहुंचा।

सेक्टर 14 की ग्रीन बेल्ट पर कबाड़, कचरा बीनने वालों ने कब्जा कर रखा है, ये सैकड़ों परिवार न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि चोरी की बिजली से इनकी दर्जनों झुग्गियां रौशन हैं। टीवी, पंखा, फ्रिज जैसी सुविधाएं चोरी की बिजली से धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं। इन परिवारों ने ग्रीन बेल्ट ही नहीं उजाड़ी खुले में शौच कर गंदगी भी फैलाई जा रही है। बीन कर लाए गए कचरे में से कीमती धातु आदि निकालने के लिए यहां भी छोटे-मोटे ढेरों में रोजाना आग लगाई जाती है।

स्थानीय निवासियों द्वारा बिजली निगम से लेकर प्रशासन तक सबसे शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। अवैध बिजली के तार काट कर ले जाने के बजाय बिजली निगम के अधिकारी इन झुग्गियों से वसूली कर मुफ्त बिजली जलाने का वरदान देते हैं। बदनीयत और भ्रष्ट अधिकारियों की लूट कमाई की नीति से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कबाड़ी तो फल फूल रहे, आम जनता, उद्यमी, कारोबारी, दुकानदार बर्बाद हो रहे हैं।

बजबजाती व्यवस्था से ....

पेज एक का शेष

हॉस्पिटल ले गया। जहां डॉक्टरों ने प्रभुनाथ के इलाज के नाम पर डेढ़ लाख रुपये लूट लिए लेकिन उनकी जान बचाने के कोई प्रयत्न नहीं किए, प्रभुनाथ की मौत हो गई।

पीड़ित गुड़िया का आरोप है कि हत्यारोपी पक्ष का तिगांव थाने में काफी रसूख है। इंस्पेक्टर दलबीर को हालात की जानकारी थी बावजूद इसके उसने पेशबंदी की कोई कार्रवाई नहीं की, आरोपियों को पाबंद नहीं किया।

यह भी आरोप है कि तिगांव पुलिस ने आरोपियों को बचाने की नीयत से एफआईआर में यौन उत्पीड़न की धाराएं नहीं लगाईं जबकि लड़कियों का यौन उत्पीड़न हुआ था। इसी तरह पुलिस मुख्य आरोपी राजेश और कर्मबीर को तफ्तीश में बाहर करने की साजिश रच रही है, यही कारण है कि उन्हें आज तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।

हालांकि पुलिस आयुक्त ने मामले की जांच क्राइम ब्रांच डीएलएफ को सौंप दी है लेकिन इसने भी अभी तक मुख्य आरोपी कर्मबीर और राजेश को नहीं पकड़ा है। पीड़ित महिला का कहना है कि सीएआईए में वीरेंद्र नागर नाम का कोई थानेदार है जो हत्यारोपियों की पूरी पैरवी कर रहा है। सरपंच होने के कारण हत्यारोपी के परिवार की प्रशासन और राजनेताओं में भी अच्छी पैठ है इसी वजह से कार्रवाई हो ही नहीं रही है।

पीड़ित परिवार का दावा है कि आरोपी राजेश और कर्मबीर गांव के लड़कों से कह रहे हैं कि प्रभुनाथ की हत्या का जिम्मा अपने सिर ले लो, लाखों रुपये दूंगा, पुलिस जांच में साफ निकलवाने की भी गारंटी दी जा रही है।

हत्या और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराध में पुलिस का आरोपियों के हक में काम करना कानून-व्यवस्था की सड़ती गलती व्यवस्था को ही दर्शाता है।

केवल पाठकों के दम पर चलने वाले इस अखबार को सहयोग देकर अपनी आवाज को बुलंद रखें।

मज़दूर मोर्चा- खाता संख्या- 451102010004150

IFSC Code : UBIN0545112

Union Bank of India, Sector-7, Faridabad

एमसीएफ का इंजीनियर सैर करने जाएगा ऑस्ट्रेलिया

फरीदाबाद (मज़दूर मोर्चा)। लूट कमाई कर शहर की सूरत बिगाड़ने वाले नगर निगम के अधिकारी अब पेयजल व्यवस्था, सीवेज सिस्टम में सुधार और प्रयोग किए गए पानी की रीसायक्लिंग सीखने ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। इससे पहले पूर्व निगमायुक्त सोनल गोयल ने भी शहर की व्यवस्था लंदन जैसी करने के लिए इंग्लैंड का दौरा किया था लेकिन वह सिर्फ मौज मस्ती ही साबित हुआ क्योंकि आज तक मैडम ने कोई रिपोर्ट ही नहीं पेश की।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार देश के विभिन्न शहरों से चुने गए अधिकारियों का एक 16 सदस्यीय दल 30 अक्तूबर को ऑस्ट्रेलिया रवाना होगा। इस दल में फरीदाबाद नगर निगम के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर नितिन कादियान को शामिल किया गया है। यह दल वहां दस दिवसीय टूर के दौरान जलवायु परिवर्तन अध्ययन, जल संरक्षण और बेकार पानी के पुनर्चक्रण का भविष्य विषय पर अध्ययन करेगा। नितिन कादयान इस टूर के दौरान गंदे पानी का दोबारा प्रयोग करने, जल संरक्षण और पेयजल की गुणवत्ता सुधार का अध्ययन करेंगे।

अच्छी बात है वो जाएं, लेकिन वो जो अध्ययन करने जा रहे हैं उसके लिए पहले यहां की पेयजल व्यवस्था, सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त होने चाहिए जो हैं नहीं। शहर को वर्तमान में 340 एमएलडी पेयजल की आवश्यकता है, निगम के 'कर्मठ' अधिकारी उसकी केवल दो तिहाई यानी 210 एमएलडी ही दे पा रहे हैं, यानी एक तिहाई जनता पानी से वंचित है। निगम के फर्जी डिग्री वाले इंजीनियरों ने पूरे शहर की छोटी बड़ी नालियों को खत्म कर उन्हें सीसी या आरएमसी सड़कों से पाट दिया, नतीजा हल्की सी बारिश में नजर आ जाता है।

शहर की मुख्य सड़कों से लेकर गलियों तक जलभराव हो जाता है जो निकासी न होने के कारण घंटों और कभी कभी दिन भर बना रहता है।

शहर की छह दशक पुरानी सीवर लाइनों को अपग्रेड करने के बजाय आरएमसी रोड के नीचे दफन कर सीवेज सिस्टम को निगम के 'काबिल' इंजीनियरों ने बर्बाद कर दिया। जल निकासी व्यवस्था का भी बुरा हाल है। सेक्टरों से लेकर, कॉलोनियों तक नालियों का पानी सड़कों पर बहता दिखता है।

आस्ट्रेलिया एक विरल आबादी वाला देश है, यहां के शहर भी खुले-खुले और व्यवस्थित बसे हुए हैं। इस महाद्वीप की अधिकतर भूमि समुद्रतल से नीचे होने के कारण यहां उत्स्रुत कुंए (ऑर्टिजियन वेल) अधिकता में पाए जाते हैं यानी ऐसे कुंए जिनसे पानी अपने आप बाहर निकलता रहता है। इसके विपरीत फरीदाबाद भूजल उपलब्धता के मामले में क्रिटिकल जोन में आता है यानी इस इलाके में भूजल का दोहन रिचार्ज होने से अधिक मात्रा में किया जा रहा है। इस संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया के जल संसाधन और यहां के जल संसाधनों में जमीन आसमान का अंतर है।

रही बात इस्तेमाल के बाद बेकार हुए पानी को रिसायकल कर दोबारा इस्तेमाल योग्य किए जाने की तो इस मामले में भी निगम के कर्मचारी नाकाबिल ही साबित हुए हैं। शहर में जितने भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं वह बनने के बाद से चले ही नहीं और बिना काम किए ही कंडम घोषित हो चुके हैं। इक्का-दुक्का चले भी तो वे अपनी पूर्ण क्षमता में काम नहीं कर रहे। ये एसटीपी तो पानी को शोधित करने के बजाय भ्रष्ट निगम अधिकारियों के लिए जेनरेटर खर्च, मरम्मत आदि के नाम पर धन लूटने के संसाधन बने हुए हैं।

निगम अधिकारियों को अध्ययन के नाम पर विदेशों के टूर का नाटक करने से पहले अपनी व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए। जब सभी आधारभूत व्यवस्थाएं चाक चौबंद होंगी तो उनमें सुधार करने के लिए एडवांस अध्ययन करने का औचित्य भी साबित होगा, अन्यथा यह टूर भी जनता की गाढ़ी कमाई पर सैर सपाटे से ज्यादा कुछ साबित नहीं होने वाला।